खंड १४ नंबर ४ अक्तूबर २०१८

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

दसवां दिल्ली संवाद : भारत–आसियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना

भारत की माननीया विदेश मंत्री दसवें दिल्ली संवाद के दौरान आसियान के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ उपस्थित हैं।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली; आसियान सचिवालय, जकार्ता; आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में 19-20 जुलाई 2018 को दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण आयोजित किया। 10वें दिल्ली संवाद का विषय 'भारत–आसियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना' था। भारत की माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) और श्री एम. जे. अकबर ने क्रमशः मंत्रिस्तरीय और विशेष पूर्ण सत्रों में मुख्य भाषण दिए। राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व) ने उद्घाटन भाषण दिया और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आसियान के सदस्य देशों के कई वरिष्ठ मंत्रियों सहित लगभग 300 प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित

शेष पृष्ठ 7 पर जारी.....

दिल्ली प्रक्रिया–4 के जरिए बीएपीए+40 की ओर

दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) और त्रिकोणीय विकास सहयोग (टीडीसी) की अवधारणा की दिशा में हालिया प्रयास अपनी सामान्य शुरुआत के बाद अब लंबा सफर तय कर चुके हैं और इसके साथ ही ये वैश्विक विकास से जुड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में उभर कर सामने आए हैं। विभिन्न संस्थानों जैसे नवीन विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक परिदृश्य में एसएससी

शेष पृष्ठ 2 पर जारी.....

73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देती हुईं।

Continued from page 1...

सम्मेलन में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट विचार–विमर्श करते हुए।

के बढ़ते प्रभाव के गवाह हैं। 4 जून, 2018 को प्रिटोरिया में एसएससी पर पेश किए गए हालिया आईबीएसए घोषणापत्र में एसएससी के सिद्धांतों को समूह के सदस्य देशों द्वारा विकास सहयोग के आधार स्तंभ के रूप में दोहराया गया है। ब्यूनस आयर्स कार्य योजना (बीएपीए 40) से जुड़ा संयुक्त राष्ट्र का आगामी स्मरणीय सम्मेलन एसएससी के इस विविध और सक्रिय इतिहास पर टिका हुआ है।

एसएससी के सैद्धांतिक आधार पर विचार करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरआईएस ने विदेश मंत्रालय, दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी), एनईएसटी और एफआईडीसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 13–14 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में 'दक्षिणीय सहयोग और बीएपी+40 सैद्धांतिक दृष्टिकोण और अनुभवजन्य वास्तविकताओं' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में एसएससी की सैद्धांतिक बारीकियों को मजबूत करने और विकास सहयोग की वैश्विक समझ का विस्तार करने – इसकी वैचारिक रूपरेखा और प्रासंगिक अनुभवजन्य मान्यताओं पर फोकस किया गया। इस साल 'दिल्ली प्रक्रिया' में जिस सैद्धांतिक निर्माण पर विचार–विमर्श किया गया उसमें एसएससी के कुछ गैर–विचारणीय सिद्धांतों पर एक रूपरेखा तैयार करने एवं एक समझौता करने और एसएससी में शामिल तौर–तरीकों के सैद्धांतिक प्रतिरूपण के रूप में विकास संविदा के उद्भव पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस ने उद्घाटन भाषण दिया और प्रो. अमिताभ आचार्य, विशिष्ट प्रोफेसर, अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। श्री जॉर्ज चेडिक, निदेशक, यूएनओएसएससी; माननीय श्री डैनियल चुबुरु, राजदूत, अर्जेंटीना गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली और श्री टी.एस. त्रिमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण के साथ सम्मेलन का मान बढ़ाया।

सम्मेलन में चर्चाएं दक्षिणीय सहयोग के लिए एक नई सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करने पर हुईं जो या तो मुद्रावादी एवं संरचनात्मक विचारधाराओं के एक संकर के रूप में विकसित हो सकती है या अर्थशास्त्र में एक नया दृष्टिकोण बना सकती है। जहां एक तरफ मुद्रावादियों के साथ दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित होता है जो विकास और तरक्की को वृहद आर्थिक स्थिरता के साथ जोड़ कर देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ संरचनावादियों के साथ दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित होता है जो यह मान कर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना दरअसल सतत विकास करने के लिए जनसंख्या की निर्माण क्षमता के मामले में कहीं अधिक मायने रखती है, भले ही यह अल्प अवधि में वृहद आर्थिक स्थिरता की कीमत पर हो। चाहे यह एक संकलन हो या एक नया दृष्टिकोण, विचार–विमर्श के दौरान इस पर विशेष जोर दिया गया कि एक सैद्धांतिक रूपरेखा में दक्षिणीय सहयोग के मूल सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए।

इस सम्मेलन में एसएससी के एक स्तंभ के रूप में घरेलू क्षमता के निर्माण के महत्व को सामूहिक रूप से रेखांकित किया गया, न सिर्फ इसलिए कि विभिन्न देश अपनी स्वयं की विकास गाथा का श्रेय पा सकें, बल्कि उत्तर–दक्षिण, दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग से भी बेहतर लाभ उठाया जा सके।

एसएससी के प्रभाव के आकलन पर विचार–विमर्श के दौरान व्यापक और सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण के दो स्तर उभर कर सामने आए। व्यापक स्तर पर विश्लेषण बहु–विषयक तरीके से राउल प्रेबिश और अल्बर्ट हिर्शमेन के कार्यों से हासिल असमानता में कमी पर केंद्रित योगदानों से संबंधित है। सूक्ष्म स्तर

के विश्लेषण के तहत इस पर गौर किया जाता है कि दक्षिणीय सहयोग से जुड़ी पहल विभागीय प्रक्रिया यानी स्थानीय स्थितियों और विभिन्न व्यक्तिगत विशिष्टताओं के प्रति सम्मान में किस तरह से योगदान करती हैं। एसएससी के अंतर्गत होने वाले प्रमुख वाद–विवादों के तहत इन प्राथमिक प्रश्नों पर गौर किया जाता है : आकलन पद्धति का आधार क्या होना चाहिए और एसएससी के लिए लेखांकन का स्वरूप क्या होना चाहिए? ये प्रश्न एक दूसरे से स्वतंत्र या अलग नहीं हैं और ये अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। प्रभाव के आकलन में एसएससी के सिद्धांतों को लागू करने की संभावना से प्रारंभिक निदान में सुधार के अवसर बढ़ जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करना संभव हो पाता है और इसके साथ ही कहीं ज्यादा निष्पक्ष रूप से प्रभावों का आकलन हो पाता है। ऐसे में स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़ी परियोजनाओं का स्वामित्व यहां तक कि समुदाय स्तर पर भी संभव हो पाएगा। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने यह बात रेखांकित की कि एसएससी सूक्ष्म स्तर पर की जाने वाली परियोजना संबंधी पहलों के स्तर पर सबसे अच्छा काम करता है।

इस दौरान किफायती दर पर विकास वित्त की उपलब्धता और और इसके विभिन्न स्रोतों पर भी चर्चाएं की गईं। इन सत्रों के दौरान यह पाया गया कि व्यापार प्रवाह को स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन निवेश रणनीतिक होते हैं और इनमें क्षमता निर्माण की संभावनाएं निहित होती हैं जो विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा की प्रभावशीलता को समझना उनके लिए जरूरी है, ताकि उन्हें नाजुक स्थिति का सामना न करना पड़े। अंतरराष्ट्रीय रुपया अदला–बदली एक्सचेंज एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सशर्त होने या इसके न होने से ऋण संबंधी जोखिम, .ऋणग्रस्तता और विकास सहयोग के अन्य रूपों विशेषकर आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) से उत्पन्न होने वाली वित्तीय अनिश्चितताओं की तुलना में एसएससी का विशिष्ट स्वरूप परिभाषित होगा। ज्ञान प्रवाह विकास के

सम्मेलन का उद्घाटन सत्र प्रगति पर है।

मोर्चे पर बेहतरी को चिन्हित करता है और प्रक्रिया को अंतर्निहित ढंग से सुधारने के लिए क्षमता का निर्माण करता है। सिविल सोसायटी संगठनों को भी मानकों को तय करने और सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच सफल संपर्क बनाने से जुड़ी एसएससी की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभानी है।

इस सम्मेलन ने निरंतर संवाद के लिए रास्ते खोल दिए जिसका उद्देश्य जी–20 में होने वाले वाद–विवादों के साथ–साथ 20 से 22 मार्च 2019 तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाले दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी शामिल होना है। विकासशील देशों के सामूहिक विकास के लिए कामकाज या व्यवसाय, कृषि और बुनियादी ढांचे के भविष्य का विकास बार–बार प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा था, जैसा कि जी–20 शेरपा और अर्जेंटीना के राजदूत द्वारा विशिष्ट रूप से दर्शाया गया। गोलमेज सम्मेलन के दौरान नए शोध एजेंडों को प्रस्तुत किया गया जिन्होंने ''दिल्ली प्रक्रिया+4 के चर्चारत विषयों, अर्थात प्रभाव आकलन की पद्धति और पाठ्यक्रम संबंधी शैक्षणिक पहलों को बांधे रखा। अपने लक्ष्य को बखूबी समझते हुए 'दिल्ली प्रक्रिया+4 मुख्यतः नीति निर्माताओं, सिविल सोसायटी और अकादमियों का नेटवर्क बनाने की दिशा में अग्रसर हो गई, ताकि विभिन्न हितधारकों को सामूहिक कदम उठाने के लिए एकजुट किया जा सके।

सम्मेलन का विस्तृत एजेंडा तैयार संदर्भ के लिए आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दक्षिणीय सहयोग और 'बीएपीए +40' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख पैनलिस्ट शिरकत करते हुए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस के साथ संवादात्मक सत्र

73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस के साथ एक संवादात्मंक सत्र 11 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आरआईएस, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और दिल्ली हाट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने सभी का स्वागत किया। डॉ. विधु पी. नायर, निदेशक (यूएनपी), विदेश मंत्रालय ने आरंभिक भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत का संचालन भी किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित प्रतिभागी ये थेः डॉ. बिंदेश्वर पाठक, संस्थापक, सुलभ स्वच्छता एवं सामाजिक सुधार आंदोलन; सुश्री सुनंदा के. रेड्डी, अध्यक्ष एवं परामर्शदाता, केयरनिधि;

भारत और सतत विकास लक्ष्यः आगे की राह' पर विशेष एसडीजी खंड 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस को पेश किया गया।

सुश्री मीनु वाडेरा, कार्यकारी निदेशक, आज़ाद फाउंडेशन; सुश्री कविता और श्री गौरव चौहान, नवधान्य; और सुश्री स्नेहा डे, गूंज। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस ने विशेष भाषण दिया। इस अवसर पर आरआईएस ने प्रतिष्ठित मेहमानों को एसडीजी पर अपना विशेष खंड *'भारत और सतत विकास लक्ष्यः आगे की राह'* भी पेश किया। डॉ. बीना पांडे, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

नीली अर्थव्यवस्था पर दूसरी आसियान–भारत कार्यशाला

विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय (एमएफए), वियतनाम; आसियान सचिवालय, जकार्ता; आसियान एवं पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली और आरआईएस, नई दिल्ली स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 18 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर दूसरी आसियान–भारत कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। ईआरआईए के अध्यक्ष प्रो. हिदेतोशी निशिमुरा और भारत में वियतनाम के राजदूत माननीय श्री टोन सिन्ह थान्ह ने आरंभिक भाषण दिए। राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), एमईए ने मुख्य भाषण दिया। कार्यशाला में आसियान

राजदूत मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस और राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व) प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ उपस्थित हैं।

के प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, आसियान एवं भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य न्हा ट्रांग, वियतनाम में 24–25 नवंबर 2017 को ब्लू इकोनॉमी पर आयोजित की गई प्रथम आसियान–भारत कार्यशाला में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाना और आसियान–भारत

शेष पृष्ठ 9 पर जारी.....

वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका

आरआईएस ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) ; बर्लिन स्थित डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट (डीओसी); और दैनिक भास्कर के साथ मिलकर 3 जुलाई 2018 को नई दिल्ली स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में डॉ. जगदीश सेठ, चार्ल्स एच. केल्स्ताड, मार्केटिंग के प्रोफेसर, गोइजुवेटा बिजनेस स्कूल, एमोरी यूनिवर्सिटी, अटलांटा, अमेरिका द्वारा 'वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका' पर सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया।

डॉ. जगदीश सेठ भू–राजनीतिक विश्लेषण में अपने विद्वत्तापूर्ण योगदान के लिए प्रख्यात हैं। उन्हें सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इलिनोइस विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, एमआईटी, और एमोरी विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध में 50 वर्षों से भी अधिक का लंबा संयुक्त अनुभव है।

'वैश्विक संदर्भ में भारत–रूस संबंधों' पर रिपोर्ट पेश करते हुए।

डॉ. विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसका शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और एनएमएमएल के निदेशक श्री शक्ति सिन्हा के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट (डीओसी) के प्रबंध परियोजना निदेशक श्री पूरन चंद्र पांडेय ने प्रारंभिक भाषण दिया। श्री दीपक द्विवेदी, बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य संपादक, दैनिक भास्कर ने विशेष भाषण दिया।

इस अवसर पर 'वैश्विक संदर्भ में भारत–रूस संबंध' पर रिपोर्ट भी जारी की गई जिसे आरआईएस और डीओसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया।

एफआईडीसी का 'विकास सहयोग के लोकतंत्रीकरण' पर गोलमेज सम्मेलन

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हाल ही में अपनाए जाने से विकास सहयोग को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने में एक और व्यापक रूपरेखा जुड़ गई है जिसमें कई हितधारक शामिल हैं। इस व्यापक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) और आरआईएस ने 9 अगस्त 2018 को आरआईएस में 'बहु–हितधारक साझेदारियों के जरिए विकास सहयोग के लोकतंत्रीकरण' पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। पीआरआईए के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रोफेसर गुलशन सचदेव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; कार्ल गेर्शमैन, प्रेसीडेंट, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, अमेरिका; और प्रो. माइको इचिहारा, एसोसिएट प्रोफेसर, हितोत्सुबाशी विश्वविद्यालय, जापान इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे।

पीआरआईए के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन 'विकास सहयोग के लोकतंत्रीकरण' पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए।

प्रोफेसर सिउंगजू ली, चुंग–एंग विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया और प्रो. मिलिन्दो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस इस अवसर पर प्रमुख चर्चाकर्ता या प्रतिभागी थे। 'वैश्विक गवर्नेंस संस्थानों के लोकतंत्रीकरण' पर सत्र की अध्यक्षता श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने की।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन पूर्व उच्च स्तरीय सलाहकार बैठक

आरआईएस ने रणनीतिक एवं सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान संस्थान (आईएसएसआर) और पवेलियन ग्रुप के साथ मिलकर 2–3 अगस्त 2018 को काठमांडू में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन पूर्व उच्च स्तरीय सलाहकार बैठक आयोजित की। प्रोफेसर डॉ. गोविंद नेपाल, कार्यवाहक अध्यक्ष, आईएसएसआर नेपाल ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय श्री प्रदीप कुमार ग्यावली, विदेश मंत्री, नेपाल इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। बाद में समूह ने नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की।

नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली के साथ अनेक प्रतिभागी।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। बांग्लादेश की राजदूत सुश्री मैशफी बिनटे शम्स; भारत के राजदूत श्री मनजीव सिंह पुरी; श्रीलंका की राजदूत सुश्री डब्ल्यू. स्वर्णलता परेरा; म्यांमार के राजदूत श्री यू. टुन नेई लिन; श्रीलंका एवं मालदीव में नेपाल के राजदूत प्रोफेसर डॉ. बिश्वंभर पयाकुर्यल और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बिम्सटेक एवं सार्क) श्री पीयूष श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। सलाहकार बैठक की प्रमुख सिफारिशें 26 अगस्त 2018 को नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को प्रस्तुत की गईं।

गांधी–मंडेला विरासत – आगे की राह

दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग के नामित उच्चायुक्त माननीय डॉ. एच एन मांझिनी विशेष भाषण देते हुए।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती मनाए जाने से पहले आरआईएस ने दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली, गांधी पीस फाउंडेशन और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 26 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम "गांधी–मंडेला विरासतः आगे की राह' का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री शक्ति सिन्हा, निदेशक, एनएमएमएल और श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली के नामित उच्चायुक्त माननीय डॉ. एच एन मांझिनी ने इस अवसर पर विशेष भाषण दिया।

इंडिया फाउंडेशन के अध्यएक्ष श्री राम माधव ने मुख्य भाषण दिया। गांधी शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, ने भी गांधी–मंडेला विरासत पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

दसवां दिल्ली संवाद : भारत–आसियान समुद्री सहयोग....
पृष्ठ 1 से जारी

विद्वानों, प्रोफेशनलों राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कारोबारियों, व्यावसायिक संघों इत्यादि ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण दो दिवसीय आयोजन था, जिसमें पूर्ण एवं विशेष पूर्ण सत्र के अलावा एक मंत्रिस्तरीय सत्र भी शामिल था। पूर्ण सत्र में आसियान–भारत साझेदारी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं सहित प्रमुख विषयों जैसे कि कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर (3सी) को शामिल किया गया। विशेष पूर्ण सत्र में भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विशेष भाषण के साथ भारत के विदेश राज्य मंत्री ने मुख्यं भाषण दिया। मंत्रिस्तरीय सत्र में भारत की विदेश मंत्री का मुख्य भाषण शामिल था और इसके साथ ही आसियान के प्रत्येक सदस्य देश और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख के विशेष भाषण भी शामिल थे। पूर्ण सत्रों में शामिल प्रमुख विषय ये हैं: आसियान के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर की भूमिका, सामाजिक–सांस्कृतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाना, भारत–आसियान साझेदारी एवं उभरती वैश्विक व्यवस्था, समुद्री सहयोग: भारत–आसियान साझेदारी के लिए एक नई रूपरेखा, आसियान–भारत व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी, विकास सहयोग, एसएमई और क्षेत्रीय विकास, पर्यटन सहयोग और स्मार्ट सिटी का निर्माण।

'दसवां दिल्ली संवाद' समापन सत्र के साथ समाप्त हो गया जिस दौरान 'आगे की राह' पर फोकस किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार ने की। भारत में थाईलैंड के राजदूत श्री चुटिन्टॉर्न गोंगस्की ने विशेष भाषण दिया। भारत के आवास एवं शहरी मामलों के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भी विशेष भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) 10वें दिल्ली संवाद के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गोलमेज सम्मेलन पर आयोजित विशेष पूर्ण सत्र में मुख्य भाषण देते हुए।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी समापन सत्र के दौरान भारत में थाईलैंड के राजदूत माननीय श्री चुटिन्टॉर्न गोंगस्की, आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे और आसियान के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित हैं।

प्रोटीन कुपोषण से निपटने के लिए दाल क्रांति

'प्रोटीन कुपोषण से निपटने के लिए दाल क्रांति' पर ग्यारहवां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 7 अगस्त 2018 को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन मोहापात्रा ने दिया, तथा डॉ. राजेंद्र सिंह परोदा, पूर्व डीजी, आईसीएआर और अध्यक्ष, कृषि विज्ञान के विकास के लिए ट्रस्ट (टीएएएस) ने इसकी अध्यक्षता की। वर्तमान पदभार संभालने से पहले डॉ. मोहापात्रा प्रतिष्ठित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक–सह–कुलपति थे। इससे पहले वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (पूर्व में सीआरआरआई), कटक के निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

डॉ. राजेंद्र सिंह परोदा, पूर्व डीजी, आईसीएआर और अध्यक्ष, कृषि विज्ञान के विकास के लिए ट्रस्ट (टीएएएस) व्याख्यान देते हुए।

डॉ. राजेंद्र सिंह परोदा एक कृषि वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में वह कृषि विज्ञान के विकास के लिए ट्रस्ट (टीएएएस) के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्व महानिदेशक और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) में सचिव हैं।

स्वास्थ्य सेवा के लिए किफायती नवाचार

'स्वास्थ्य सेवा के लिए किफायती नवाचार' विषय पर बारहवां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 10 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव और आईसीएमआर के डीजी प्रो. बलराम भार्गव ने दिया। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने की। प्रो. भार्गव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी या हृदय रोग विज्ञान के प्रोफेसर हैं और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन (एसआईबी) के स्टेनफोर्ड इंडिया बायोडिजाइन सेंटर के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव और आईसीएमआर के डीजी प्रो. बलराम भार्गव व्याख्यान देते हुए।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम की स्थापना विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह फोरम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अंतर–अनुभागीयता और व्याख्यान को ध्यान में रखते हुए विषयक संबंधी सीमाओं से परे जाएगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार करने के साथ–साथ सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ी बहस का सामान्यीकरण करने और उत्तरदायी अनुसंधान एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर आम जनता को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से ही मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई है। सहयोगी या सहयोगात्मक संस्थान ये हैं – अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), ऊर्जा संसाधन संस्थान (टेरी), विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई), उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत–फ्रांसीसी केंद्र (सीईएफआईपीआरए), विज्ञान प्रसार और भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी)।

'एचएलपीएफ, 2018' में आरआईएस की भागीदारी

आरआईएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10–13 जुलाई, 2018 के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ), 2018 की बैठकों में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और सहायक प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा शामिल थे। आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी की अगुवाई वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त राष्ट्र भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त रूप से एचएलपीएफ की बैठकों में भाग लिया। इस यात्रा के एक हिस्से के रूप में भारत और वैश्विक स्तर पर विशेषकर विकासशील देशों में एसडीजी की प्राप्ति हेतु साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्नन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। इसने आरआईएस को वर्ष 2015 में हुए सतत विकास शिखर सम्मेलन और वर्ष 2017 में एचएलपीएफ के दौरान ठीक इसी तरह की सहभागिता को जारी रखते हुए इन एजेंसियों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर दिया।

आरआईएस ने इन विषयों पर आयोजित एचएलपीएफ की महत्वएपूर्ण समीक्षा बैठकों में भाग लिया : 'एसडीजी के कार्यान्वयन की समीक्षाः एसडीजी 11 – शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ़ एवं टिकाऊ बनाना' और 'एसडीजी के कार्यान्वयन की समीक्षाः एसडीजी 17 – कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ बनाना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी में नई जान फूंकना।' आरआईएस की टीम ने 'विकास के लिए वित्त पोषणः प्रगति और संभावनाएं 2018' पर अलग से आयोजित की गई एक बैठक में भी भाग लिया। आखिर में, आरआईएस के महानिदेशक ने 13 जुलाई 2018 को दक्षिणीय सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अलग से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया जिसका विषय था 'एसडीजी के दौर में दक्षिणीय सहयोग के प्रभाव को अंकित करना।'

vkfèkdkfjd nkor

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने उपर्युक्त संलग्नताओं के अलावा 14 जुलाई 2018 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन सहित आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी के सम्मान में और संयुक्त राष्ट्र एवं उससे परे साझेदार एजेंसियों के लिए न्यूयॉर्क में रात्रिभोज की मेजबानी की, ताकि विभिन्न देशों के साझेदार संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों में एसडीजी पर सहभगिता के दायरे को व्यापक बनाया जा सके।

उच्च स्तरीय भोज में भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी; संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस; संयुक्त राष्ट्र हैबिटैट की कार्यकारी निदेशक सुश्री मईमुना मोहम्मद शरीफ; प्रो. अरविंद पनगढ़िया, कोलंबिया विश्वविद्यालय; संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद अकबरुद्दीन; संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत तन्मय लाल; भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक श्री यूरी अफानासीव; दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक श्री जॉर्ज चेडीक; राजदूत लक्ष्मी पुरी इत्यादि ने शिरकत की। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न विकासशील देशों के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रभागों के प्रमुख/प्रतिनिधि भी इस भोज में मौजूद थे।

नीली अर्थव्यवस्था पर दूसरी आसियान–भारत कार्यशाला

....पृष्ठ 4 से जारी

रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख पहलू के रूप में समुद्री क्षेत्र में आसियान–भारत सहयोग में प्रगति करने संबंधी राजनेताओं के विजन को साकार करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को आगे बढ़ाना था। कार्यशाला के आखिर में चिन्हित की गई विशिष्ट गतिविधियां और क्षेत्र, जिनमें आसियान एवं भारत आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, उस आधार के रूप में काम करेंगे जिन पर आसियान और भारत इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना विकसित कर सकते हैं। कार्यशाला के निष्कर्ष के बारे में जानकारी 'दसवें दिल्ली संवाद' के मंत्रिस्तरीय सत्र के दौरान दी गई जिसका आयोजन 19–20 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में किया गया था। कार्यशाला को चार सत्रों में विभाजित किया गया था, ताकि उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ब्लू इकोनॉमी पर गहन चर्चा संभव हो सके जिनमें आसियान और भारत आपस में सहयोग कर सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये चार सत्र इन विषयों पर आयोजित किए गए थेः नीली अर्थव्यवस्था एवं समुद्री कनेक्टिविटी; नीली अर्थव्यवस्था के लिए मददगार प्रौद्योगिकी; नीली अर्थव्यवस्था का विकास एवं समुद्री सुरक्षा व कूटनीति, और नीली अर्थव्यवस्था।

आखिर में, समापन सत्र के दौरान भारत में वियतनाम के राजदूत माननीय श्री टोन सिन्ह थान्ह ने समापन भाषण दिया। श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान एमएल), विदेश मंत्रालय ने समापन सत्र को संबोधित किया, जबकि डॉ. प्रबीर डे, एआईसी के समन्वयक ने कार्यशाला का सार प्रस्तुत किया और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन किया।

व्यापार और स्थायित्व पर नया पाठ्यक्रम

'व्यापार और स्थायित्व' पर आईटीईसी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागीगण आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ उपस्थित हैं।

आरआईएस ने नई दिल्ली में 9 से 20 जुलाई, 2018 तक 'व्यापार और स्थायित्व' पर प्रथम आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न विकासशील देशों के मध्य स्तर के सरकारी अधिकारियों, नीति प्रोफेशनलों और शिक्षाविदों सहित 25 से भी अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम में व्यापक रूप से विभिन्न विषयों जैसे कि उत्पादन एवं व्यापार, नियामकीय रूपरेखा, जैव विविधता इत्यादि को शामिल किया गया। आरआईएस के संकाय सदस्यों एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने इन विषयों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य के बारे में बहुमूल्य जानकारियां दीं। यह कार्यक्रम प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस द्वारा समन्वित किया गया। कार्यक्रम का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सतत विकास लक्ष्यों पर नया पाठ्यक्रम

एसडीजी पर आईटीईसी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागीगण आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ उपस्थित हैं।

आरआईएस ने नई दिल्ली में 6 से 17 अगस्त, 2018 तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में 'सतत विकास लक्ष्यों' पर आईटीईसी के क्षमता–निर्माण पाठ्यक्रम का पहला संस्करण आयोजित किया।

24 देशों के मध्य स्तर के सरकारी अधिकारियों/राजनयिकों, नीति प्रोफेशनलों और विद्वानों सहित 32 से भी अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम में व्यापक रूप से इन मॉड्यूल को कवर किया गया – एसडीजी एवं राष्ट्रीय रणनीति; एसडीजी एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दे; एसडीजी एवं आर्थिक विकास; पर्यावरणीय स्थिरता; संबंधित व प्रासंगिक मुद्दे एवं कार्यान्वयन के साधन और एसडीजी के लिए वैश्विक साझेदारी व स्थानीयकरण से जुड़े प्रयास।

आरआईएस के आंतरिक या संस्थानिक संकाय के अलावा प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को भी विभिन्न विषयों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि प्रतिभागीगण इससे लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ब्रेकफास्ट सेमिनार सीरीज

'आरसीईपी' से जुड़ी वार्ताओं के मौजूदा दौर में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए 26वां आरआईएस ब्रेकफास्ट सेमिनार 29 अगस्त, 2018 को आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी के दौरान 'आरसीईपी से जुड़ी वार्ताओं के मुद्दों' पर फोकस किया गया। वर्तमान में आरआईएस में प्रतिष्ठित फेलो एवं भारत के पूर्व वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर और आरआईएस के पूर्व वाइस चेयरमैन एवं अब सीसीआई में सेवारत राजदूत (डॉ.) वी.एस. शेषाद्रि इस अवसर पर प्रमुख वक्ता थे। उनकी प्रस्तुतियों के बाद प्रतिभागियों के साथ गहन चर्चा की गई।

इस श्रृंखला में 27वां सेमिनार 28 सितंबर 2018 को आरआईएस में 'चाबहारः एक बंदरगाह बेहद दूर?' विषय पर आयोजित किया गया। इसे श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजदूत डी.पी. श्रीवास्तव, ईरान में भारत के पूर्व राजदूत और वर्तमान में सीनियर फेलो एवं क्लस्टर लीडर, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली ने इस सेमिनार की अध्यक्षता की। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसके साथ ही चर्चा में भी हिस्सा लिया। इसी विषय पर एक नीतिगत सार–पत्र भी पेश किया गया और इसे आरआईएस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

प्रोफेसर मिलिन्दो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस द्वारा 'संवर्धन एवं विकास मॉडलः समकालीन परिप्रेक्ष्य' विषय पर 25वां ब्रेकफास्ट सेमिनार 24 जुलाई 2018 को आरआईएस में आयोजित किया गया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व निदेशक प्रो. पुलिन नायक ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की। बड़ी संख्या में प्रतिभागी इस दौरान हुए विचार–विमर्श से लाभान्वित हुए।

प्रो. सविन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 4 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित 'प्रौद्योगिकी की अगुवाई में नवाचार नीति' तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय पैनल की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- 4 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल द्वारा आयोजित 'एसडीजी 16 भारतः डेटा अंतर का मानचित्रण' नामक सीएचआरआई की नवीनतम रिपोर्ट के लांचिंग कार्यक्रम के दौरान 'एसडीजी 16 : आगे की कार्यवाही एवं समीक्षा' पर पैनल परिचर्चा का संचालन किया।
- 6 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग में आयोजित नीली अर्थव्यवस्था की मसौदा समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- 6 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में इंडिया टुडे द्वारा आयोजित 'मेक इन इंडिया उभरते उद्यमी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2018' के दौरान 'निर्यात का दोहन करनाः कौन सी चीज भारत को रोक रही है' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 11 जुलाई 2018 को न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'एसडीजी के कार्यान्वयन की समीक्षाः एसडीजी 11 – शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ़ और टिकाऊ बनाने' पर आयोजित आधिकारिक बैठक में भाग लिया।
- 13 जुलाई 2018 को न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) के दौरान 'दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' द्वारा 'एसडीजी–17 के लिए डेटा' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 18 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में टेरी द्वारा 'कृषि लाभप्रदता और स्थिरता के लिए गठबंधन (कैप्स)' पर आयोजित संकल्पना बैठक के दौरान 'कृषि में प्रौद्योगिकी' पर आयोजित सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 3 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग में 'नीली अर्थव्यवस्था पर संचालन समिति' की पहली बैठक में भाग लिया।
- 5 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित TEDxFMS में 'एक विश्व के लिए आगे बढ़नाः वित्त पोषण के सामाजिक जुड़ाव' पर एक प्रस्तुति' दी।
- 10 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन इंडिया सेंटर द्वारा 'एशिया में लोकतांत्रिक सहयोगः भारत और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित कार्यशाला में ''लोकतंत्र संवर्धन में भारत के योगदान'' पर हुए विशेष सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 24 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर राष्ट्रीय समिति' की बैठक में भाग लिया।
- 29 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय समुद्री नीति पर मसौदा समिति' की चौथी बैठक में भाग लिया।
- 31 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के प्रबंधन बोर्ड की 29वीं बैठक में सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 5 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित वर्ष 2018–19 के लिए सीआईआई अफ्रीका समिति की बैठक में भाग लिया।
- 11 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) द्वारा आयोजित भारतीय कृषि आउटलुक फोरम 2018 में 'कृषि व्यापार नीति और हालिया घटनाक्रमों' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 14 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित 'सामरिक पड़ोस में रचनात्मक कारकों के रूप में व्यापार, निवेश और वित्त की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 14 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग में आयोजित 'लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा और शिपिंग (वाहनांतरण या ट्रांस–शिपमेंट सहित) पर कार्य दल की पहली बैठक में भाग लिया।
- 17 सितंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में डीआईई/जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा 'जी–20 में 2030 एजेंडे के राष्ट्रीय कार्यान्वयन' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 17 सितंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में डीआईई/जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा 'जी20 क्यों : वैश्विक विकास के लिए अफ्रीका सहयोग से जुड़े मुद्दों' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे। '
- 18 सितंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय द्वारा 'दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन' के परिणाम दस्तावेज के लिए अवयवों' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

प्रो. टी.सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- एमएनएलयू, नागपुर और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) द्वारा 10 जुलाई, 2018 को विपो–इंडिया समर स्कूल में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पेटेंट और रसगुल्ला के जिज्ञासु मामले' पर आयोजित सत्रों में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 18 अगस्त, 2018 को पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के पूरक एवं एकीकृत स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 'आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अनुकूल माहौल बनाने' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और इसके साथ ही 'गवर्नेंस एवं वित्त पोषण' और 'सामाजिक विज्ञान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य' पर प्रस्तुतियां दीं।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

सलाहकार

- 13 सितंबर 2018 को बर्लिन में आयोजित टीए कार्यशाला में 'भारत में प्रौद्योगिकी आकलन' पर व्याख्यान दिया।
- 14 सितंबर 2018 को बर्लिन में आयोजित 'आरआरआई अभ्यास परियोजना बैठक' में एक प्रस्तुति दी।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

डॉ. प्रियदर्शी दाश
सहायक प्रोफेसर

- 13–14 सितंबर, 2018 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित पांचवें भारत–मध्य एशिया संवाद के दौरान 'भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार एवं निवेश के संवर्धन के वाहकों के रूप में मध्य एशिया में कनेक्टिविटी संपर्कों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 13–14 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में 'दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग: सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और अनुभवजन्य वास्तविकताओं' पर दिल्ली प्रक्रिया – 4 में 'स्थानीय मुद्रा में व्यापार' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2–3 अगस्त, 2018 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन पूर्व परामर्श बैठक में पैनल परिचर्चा के दौरान 'बिम्सटेक में प्राथमिकताओं' पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. दुरइराज कुमारसामी
सलाहकार, आरआईएस स्थित एआईसी

- 26–27 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, वियतनाम अध्ययन केंद्र, समाजवादी गणराज्य वियतनाम के दूतावास और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत–वियतनाम सुदृढ़ आर्थिक संबंधों' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'भारत और वियतनाम के बीच क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला में सुधार' पर एक प्रस्तुति दी।
- 14 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग में 'बीबीआईएन में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संभावित नकारात्मक पहलू' पर आयोजित गोलमेज परिचर्चा में भाग लिया।

श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने 12–14 अक्टूबर 2018 को ओमान के मस्कट में आयोजित आईआईएसएस–एनईएसए दक्षिणी एशिया सुरक्षा सम्मेलन के दौरान विशेषकर अफगानिस्तान पर परिचर्चाओं वाले दूसरे सत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए।

भारतीय विज्ञान कूटनीति के लिए फोरम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से विज्ञान कूटनीति पर आरआईएस–एनआईएएस के संयुक्त कार्यक्रम के तहत 'भारतीय विज्ञान कूटनीति के लिए फोरम (एफआईएसडी)' को 4 अक्टूबर, 2018 को लांच किया गया। एफआईएसडी ज्ञान साझा करने के लिए वैज्ञानिकों, राजनयिकों, रणनीतिक विचारकों, नीति निर्माताओं, कारोबारियों और विज्ञान कूटनीति के विभिन्न पहलुओं में शामिल विद्वानों के बीच एक संपर्क बिंदु (इंटरफेस) बनाने के लिए प्रयासरत है। यह फोरम भारतीय परिप्रेक्ष्य और विश्व के विकासशील देशों की दृष्टि से विज्ञान कूटनीति को सिद्धांत एवं व्यवहार में फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। समावेशी, सतत और सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी विकास सुनिश्चित करने में विज्ञान कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। एफआईएसडी के तहत कुछ मौजूदा गतिविधियों में ये शामिल हैं : विज्ञान कूटनीति पर आरआईएस–एनआईएएस का संयुक्त कार्यक्रम; विज्ञान कूटनीति पर आरआईएस–आईटीईसी पाठ्यक्रम; विज्ञान कूटनीति एवं उत्तरदायी अनुसंधान व नवाचार (आरआरआई) के साथ–साथ आरआईएस में अन्य गतिविधियां जैसे कि ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ), भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम) और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम।

एफआईएसडी के पास एक समर्पित वेबसाइट (www.fisd.in) है, जो संयुक्त विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम की विविध गतिविधियों और प्रदेय वस्तुओं या उत्पादों को प्रदर्शित करती है। यह फोरम नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विज्ञान कूटनीति में जुटे प्रोफेशनलों के सहयोग से सृजित संसाधनों को साझा करता है। यह फोरम भारत और अन्य विकासशील देशों के वैज्ञानिकों एवं राजनयिकों के लिए क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करेगा। इसके अलावा, यह फोरम भारतीय विज्ञान कूटनीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए व्याख्यान, सेमिनार, अनुसंधान एवं परामर्श से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करेगा।

iLrd@fjikV

pkFk fcElVd f'k[kj lEeyu d fy, lQkfj'k
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

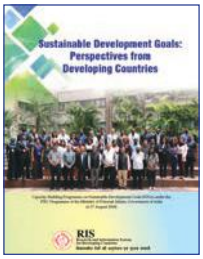

lrr fodkl y{;% fodkl'khy n'kk d ifjç{;
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

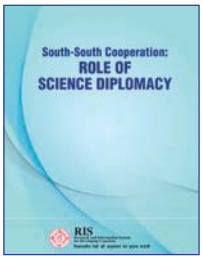

nf{k.kh; lg;kx% foKku dVuhfr dh Hkfedk
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

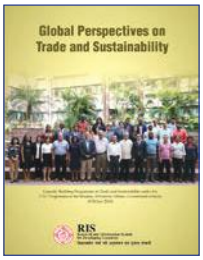

0;kikj vkj LFkkf;Ro ij ofÜod ifjç{;
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

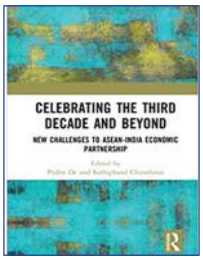

rhljs n'kd vkj mlls ijs dk dhfrxku djuk% vkfl;ku&Hkkjr vkfFkd lk>snkjh d fy, uÃ pukfr;k] çchj Ms vkj lrhign fpjfFkokr }kjk likfnr] :Vy t] 2018] vkÃ,lch,u% 9781138484788

इस पुस्तक में आसियान–भारत संबंधों की समीक्षा की गई है एवं इसमें आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपाय सुझाए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से आसियान एवं भारत के बीच आर्थिक एकीकरण के मुद्दों का उल्लेख किया गया है और इसमें नीतिगत प्राथमिकताओं, प्रभावशीलता, कार्यान्वयन की अनिवार्यताओं एवं चुनौतियों का आकलन किया गया है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में संबंधित एवं प्रासंगिक मुद्दों के विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित करने और कुछ नीतिगत निहितार्थ निकालने के प्रयास किए गए हैं। यह नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और प्रोफेशनलों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ साबित होगी।

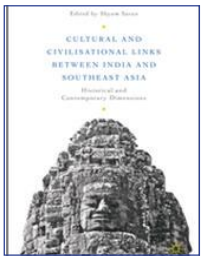

Hkkjr vkj nf{k.k&iov ,f'k;k dh chp lkL—frd ,o lH;rkxr lcek% ,frgkfld vkj ledkyhu vk;ke] ';ke lju }kjk likfnr] ikyxo edfeyu 2018] vkÃ,lch,u% 9789811073168

यह पुस्तक ऐतिहासिक और समकालीन आयामों के विशेष संदर्भ के साथ दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों पर विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) द्वारा किए गए अध्ययन को प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में प्राचीन व्यापार एवं समुद्री संपर्कों, चोल साम्राज्य एवं दक्षिण–पूर्व एशिया, धार्मिक आदान–प्रदान (हिंदू, बौद्ध एवं इस्लामी विरासत), भाषा, लिपियों व लोककथाओं, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला एवं मूर्तिकला, वास्तुकला, भारतीय समुदाय की भूमिका, समकालीन सांस्कृतिक जुड़ाव, इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

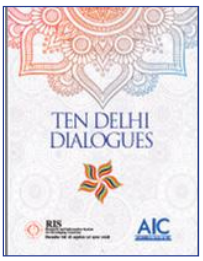

nlok fnYyh lokn] vkfl;ku&Hkkjr dæ ¼,vkÃlh½ & fodkl'khy n'kk d fy, vulèkku ,o lpuk ç.kkyh ¼vkjvkÃ,l½] 2018] vkÃ,lch,u% 8171221378

यह पुस्तक 'दिल्ली संवाद' की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में पिछले सभी दिल्ली संवादों का सार प्रस्तुत किया गया है और यह आसियान–भारत संबंधों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए तैयार संगणक के रूप में है।

vkjvkÃ,l dk ifjppk i=

- # 233 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और क्षेत्रवार प्रोत्साहनों की समीक्षा: 'मेक इन इंडिया' के लिए सबक द्वारा *सब्यसाची साहा और प्रतिभा शॉ*
- # 232 भारत में एसडीजी 4 हासिल करना: सभी के लिए मात्रात्मक शिक्षा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ना द्वारा *बीना पांडे*
- # 231 भारत में विनिर्माण क्षेत्र द्वारा मनमोहन अग्रवाल
- # 230 अवसंरचना के विकास के लिए गठबंधन करना और रणनीतियां विकसित करना द्वारा *गरिमा धीर*
- # 229 अभिनव व्यवस्थाएं और बहुपक्षवाद: नए एमडीबी की गुंजाइश पर एक प्रतिबिंब द्वारा *सब्यसाची साहा*
- # 228 अवसंरचना का वित्त पोषण करना: संसाधन जुटाना और नए साधन तलाशना द्वारा *प्रियदर्शी दाश*

uohure çdk'ku

vkjvkÃ,l dk uhfrxr lkj i=

81 चाबहारः एक बंदरगाह बेहद दूर द्वारा *सुभोमय भट्टाचार्जी*

83 आरआरआईः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य

,QvkÃVh,e vuBk iij

2 भारत में पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण द्वारा *टी.सी. जेम्स और नम्रता पाठक, सितंबर 2018, नई दिल्ली*

vkjvkÃ,l Mk;jh

खंड 14, संख्या 3, जुलाई 2018

lkmFk ,f'k;k bdku,fed tuy

खंड 19, संख्या 2 (जुलाई–दिसंबर 2018)

vkjvkÃ,l ldk; }kjk cká çdk'kuk e ;kxnku

चतुर्वेदी, सचिन। 2018 'सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक साझेदारी जरूरी' *द एशियन एज,* 9 जुलाई।

चतुर्वेदी, सचिन। 2018 'विकास संविदा' की रूपरेखा के तहत भारत के विकास सहयोग की गतिशीलता। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का वित्तपोषणः द्वार खोलना, संयुक्त राष्ट्र एमपीटीपी कार्यालय, पृष्ठ 75–78।

चतुर्वेदी, सचिन। 2018 ''बहुपक्षवाद और उभरती वैश्विक व्यवस्था के प्रति भारत का दृष्टिकोण।' *इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल,* खंड 13 (2), अप्रैल–जून 2018, पृष्ठ 128–135।

डे, प्रबीर (2018) 'बिम्सटेक को नई ऊंचाइयां हासिल करनी चाहिए', *ईस्ट एशिया फोरम,* 25 अगस्त 2018।

आरआईएस में प्रतिनिधिमंडलों का आगमन

- डॉ. जस्टिन वइसे, प्रमुख, फ्रांस के विदेश मंत्रालय में नीति नियोजन और पेरिस पीस फोरम के प्रभारी का आगमन 3 जुलाई 2018 को श्रीमती सॉलवीग ओगेरियो और श्री सामंथा बॉनबेइल, भारत में फ्रांस के दूतावास के सेकेंड काउंसलर के साथ हुआ।
- डॉ. ऋषि कुमार त्यागी, समन्वयक, कृषि जैव प्रौद्योगिकी और जैव संसाधनों पर एशिया–प्रशांत कंसोर्टियम (एपीसीओएबी), कृषि अनुसंधान संस्थानों का एशिया–प्रशांत संघ (एपीएएआरआई), बैंकॉक, थाईलैंड का आगमन 26 जुलाई 2018 को हुआ। .
- सुश्री हुआंग यिहुआ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग (आईडीसीपीसी) के अनुसंधान कार्यालय की उप महानिदेशक की अगुवाई में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का आगमन 26 सितंबर 2018 को हुआ। इसके सदस्यों में ये शामिल थेः सुश्री वांग जियाओइंग, प्रभाग निदेशक, अनुसंधान कार्यालय, आईडीसीपीसी; श्री वू हैंग, द्वितीय सचिव, अनुसंधान कार्यालय, आईडीसीपीसी।
- तंजानिया/मोजाम्बिक के विदेश संबंध केंद्र (सीएफआर) के प्रतिनिधिमंडल का आगमन 14 अगस्त, 2018 को हुआ। इसका नेतृत्व सीएफआर की शासी परिषद के अध्यक्ष राजदूत ओम्बेनी वाई. सेफ़्यू ने किया। इसके सदस्यों में ये शामिल थेः माननीय श्री बराका एच. लुवांडा, तंजानिया के उच्चायुक्त, नई दिल्ली; डॉ. रिचर्ड मबुंडा, व्याख्याता, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीति विज्ञान विभाग, दार एस सलाम विश्वविद्यालय; डॉ. लुसी शुले, व्याख्याता (अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं टकराव संकल्प), अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति विभाग; मोज़ाम्बिक/तंजानिया का विदेश संबंध केंद्र; डॉ. बर्नार्ड अचिउला, उप निदेशक, नियोजन, वित्त और प्रशासन, तंजानिया–मोजाम्बिक विदेश संबंध केंद्र, विदेश मंत्रालय और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग।

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ई–मेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia
@RIS_NewDelhi
www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादकः तीश मल्होत्रा

आरसीईपी – क्यों और कैसे

jktho [kj
विशिष्ट फेलो, आरआईएस

सोलह राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (आरसीईपी) के लिए जारी वार्ता भारत के लिए एक चुनौती और अंतर्निहित अवसर है। दुनिया की 49 प्रतिशत आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। यह क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 29 प्रतिशत (2013) और वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल व्यापार के वैश्विक हिस्से में 27.2 प्रतिशत (2013) का योगदान करता है। भारत का निर्यात पिछले कुछ वर्षों से अपने प्रदर्शन में अस्थिरता दर्शा रहा है, चालू खाता घाटा काफी बढ़ गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत वास्तव में अपनी पारंपरिक बढ़त वाले कुछ उत्पाद क्षेत्रों में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता गंवा चुका है। कच्चे तेल की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं और घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से चिंता थोड़ी बढ़ गई है। वैसे तो घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से हमारी निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें निरंतर बढ़ने के कारण व्यापार संतुलन का बिगड़ना तय है। अतः बाजारों का विस्तार करने, प्रतिस्पर्धी क्षमता बहाल करने और व्यापार प्रवाह में निश्चितता बहाल करने के लिए ठोस प्रयास करना सरकार के लिए आवश्यक है। बताया जाता है कि चीन विनिर्माण क्षेत्र में 'कम प्रौद्योगिकी–कम पारिश्रमिक या मजदूरी' वाले क्षेत्रों से अपना मुंह मोड़ रहा है और अब अपने उत्पादों एवं सेवाओं में प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ा रहा है जिसकी बदौलत वह अपने निर्यात से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त कर रहा है। इन परिस्थितियों में भारत एवं कुछ अन्य विकासशील देशों के लिए एक अच्छा अवसर सृजित हो रहा है और 'आरसीईपी' इस अवसर को फलीभूत करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भारत के समक्ष आ रहा है।

आरसीईपी के सदस्य देशों के साथ भारत के मौजूदा व्यापार ढांचे को इन दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है – ऐसे देश जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर रखे हैं और ऐसे देश जिनके साथ भारत ने इस तरह का समझौता नहीं किया है। चीन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भारत ने अन्य सभी सदस्य देशों के साथ व्यापार समझौते कर रखे हैं। भारत एवं चीन एक अन्य क्षेत्रीय तरजीही व्यापार व्यवस्था का भी हिस्सा हैं जिसका नाम है एशिया–प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए)। यह समझौता बेहद कम महत्वाकांक्षी है और इसके तहत सिर्फ शुल्क दरों या शुल्क पर केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा, अन्य सदस्य राष्ट्रों में कुछ विकासशील देश और कुछ अल्प विकसित देश (एलडीसी) शामिल हैं। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य सदस्यों जैसे कि ईरान एवं मध्य एशिया को शामिल करने हेतु इस समझौते की सदस्यता का दायरा बढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही गैर–शुल्क मुद्दों जैसे विषयों को शामिल करने के लिए इसके प्रावधानों को विस्तृत करना चाहिए। अतः चीन के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से नियम–आधारित रूपरेखा स्थापित करने हेतु भारत के लिए आरसीईपी ही एकमात्र उपलब्ध व्यवस्था है। रणनीतिक सहयोग के जरिए विशुद्ध रूप से भू–राजनीतिक संदर्भ में बहुत कुछ इस क्षेत्र में हो रहा है। दरअसल, इस तरह की स्थिति को समझना कमोबेश असंभव है कि आखिरकार क्यों भारत जैसे विशाल आकार, महत्वाकांक्षी और आर्थिक ताकत वाला देश खुद को इस तरह की व्यवस्था से बाहर रखता है। उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत को 'आरसीईपी' से जुड़ी मौजूदा वार्ताओं में भाग लेना जारी रखना चाहिए और एक आक्रामक एजेंडे पर काम करना चाहिए, ताकि लंबे समय से बरकरार कुछ चिंताओं को दूर किया जा सके।

यही नहीं, आरसीईपी हमारी घरेलू नीतियों पर व्यापक नजर डालने का अवसर भी प्रदान करता है। जिस तरह से उद्योग जगत आरसीईपी को लेकर चिंतित है, ठीक उसी तरह से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों (सेक्टर) के लिए उत्तरदायी सरकारी विभाग भी उन संभावित सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने पर समान रूप से विरोध जता रहे हैं, जिनकी बाकायदा शुरुआत आरसीईपी कर देगा। इसके लिए अन्य गैर–सरकारी हितधारकों, विशेषकर उद्योग जगत के अलावा न केवल वाणिज्य विभाग, बल्कि इस उद्देश्य से प्रासंगिक माने जाने वाले सभी अन्य विभागों में भी उच्चस्तरीय वार्ता कौशल और प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ेगी। भारत के अलावा इस क्षेत्र में 15 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जिनमें से कम से कम 11 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में अच्छी तरह से एकीकृत हैं। ये सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर काफी फोकस करते हैं, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चेन) में काफी हद तक सहभागिता करते हैं और आपस में अच्छी तरह से एकीकृत हैं। उपर्युक्त दलीलों से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के लिए आरसीईपी में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। यह अनगिनत बाजार अवसर भी खोल सकता है और इसके साथ ही चीन की व्यापार नीति के अवांछनीय पहलुओं से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। सरकार द्वारा सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ–साथ ऊंची आर्थिक विकास दर को निरंतर बनाए रखने पर फोकस करने से भारतीय अर्थव्यवस्था की इस क्षमता पर विश्वास काफी बढ़ जाता है कि वह आरसीईपी में भारत के शामिल होने पर संभावित परिवर्तनकारी उथल–पुथल से निपटने में सक्षम साबित होगी।

इसके अलावा, अनुभवों से यह पता चलता है कि भारत का उद्योग जगत विभिन्न चुनौतियों का बहादुरीपूर्वक सामना करता है और अतीत में भी वह इन चुनौतियों से निपटने में सफल साबित हुआ है। अतः हर क्षेत्र को स्वयं ही अपना सटीक आकलन करना चाहिए, ताकि वे अपनी–अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमताओं को फिर से हासिल कर सकें। आरसीईपी से कुछ क्षेत्रों पर पड़ने वाले संभावित आरंभिक दबाव को ध्यान में रखते हुए वार्ताओं के तहत इन क्षेत्रों को समायोजित करने के ठोस तरीके ढूंढने होंगे जिससे कि आरसीईपी पर अमल के दौरान कुछ हद तक संरक्षण सुलभ हो सके। अब तक हुई वार्ताएं मुख्यतः शुल्क पर केंद्रित रही हैं। आरंभिक चरण में संबंधित पक्षों ने क्रमशः एफटीए और गैर–एफटीए साझेदारों के लिए शुल्क की दो श्रेणियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। भारत की चिंताओं को अब कुछ हद तक '80 प्रतिशत ±6 की अवधारणा पर अमल करके समायोजित किया गया है जिसका मतलब यही है कि एफटीए साझेदारों के लिए शुल्क दरों (टैरिफ) में कमी/उन्मूलन 80 से 86 प्रतिशत तक होगा, जबकि गैर–एफटीए साझेदारों के लिए शुल्क लाइनों का यह दर 74 से 80 प्रतिशत तक हो सकता है। इस दायरे में रहते हुए भारत को स्वयं के लिए एक सही दिशा तय करने की जरूरत है, ताकि एकीकरण एवं उदारीकरण के साथ–साथ उद्योग के कमजोर वर्गों के अल्पावधि संरक्षण का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सके।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी व्यापार समझौता संबंधित पक्षों के बीच केवल एक वाणिज्यिक अनुबंध होता है और वे इसमें किसी भी ऐसे प्रावधान को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो तब तक समझौते के उद्देश्यों को पूरा करता है जब तक कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है। अतः इसमें स्वरूप और सामग्री की दृष्टि से अत्यधिक लचीलापन होता है जो संबंधित पक्षों की क्षमता और इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। 'आरसीईपी' में भारत के लिए एक 'गेम चेंजर' बनने या व्यापक बदलाव लाने की भरपूर क्षमता है, लेकिन इसके लिए ठोस आधार तैयार करने और विशिष्ट कौशल की आवश्यकता है।

आरआईएस नीतिगत सारपत्र संख्या 84, अक्टूबर 2018 के कुछ अंश, जिसे श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने तैयार किया है।